भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
**राज्य सभा**
लिखित प्रश्न सं. 3183
गुरूवार, 19 मार्च, 2026/28 फाल्गुन, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

**आतिथ्य क्षेत्र में अनुचित प्रथाओं को रोकना**

**3183 सुश्री स्वाति मालिवाल:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यस्ततम अवधि, त्योहारों और प्रमुख आयोजनों के दौरान होटलों और अल्पकालिक आवास प्रदाताओं द्वारा कीमतों में अत्यधिक मूल्य-वृद्धि के मामलों का संज्ञान लिया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घरेलू पर्यटकों की संख्या, विदेशी पर्यटकों के आगमन और भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता पर ऐसी मूल्य वृद्धि के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पर्यटकों के लिए शुल्क पारदर्शिता, अनिवार्य सर्व-समावेशी मूल्य प्रकटीकरण और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र के लिए कोई रूपरेखा प्रस्तुत करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आतिथ्य क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री** **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): होटलों का संचालन मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की गतिविधि है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय केवल होटलों के स्वैच्छिक वर्गीकरण/अनुमोदन योजना के तहत, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के आधार पर, परिचालनरत होटलों का वर्गीकरण करता है।

होटल संबंधी शुल्क मांग-आपूर्ति की स्थिति के अनुसार तय की जाती हैं। होटल आवास की आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 7 अक्टूबर, 2013 को अवसंरचना संबंधी उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची अधिसूचित की, जिसमें देश में होटल के कमरों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए तीन सितारा या उससे उच्च श्रेणी के ऐसे वर्गीकृत होटल शामिल हैं, जो 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त, कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने निवेश को बढ़ावा देने और इस प्रकार आतिथ्य क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है।

होटलों के पूरक के रूप में, सरकार ने होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे कि होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएमजीयूजीए)।

भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से प्रगतिशील कानूनों को अधिनियमित करके उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स बाजारों आदि के इस नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभिन्न कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं।

*****